कुल कितनी राशि व्यय होने की संभावना है और इसका लाभ कितने व्यक्तियों/परिवारों को मिलेगा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरीधर गोमांगो) : (क) और (ख) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) तथा जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित किए जा रहे प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों की कार्यनीति में किसी बुनियादी परिवर्तन का विचार नहीं है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 1993-94 के लिए लक्ष्य निम्नानुसार है :—

(1) आई आर डी पी	— ऐसे परिवारों की संख्या, जिन्हें सहायता दी जानी है 26.50.744
(2) जे आर वाई	— सृजित किए जाने वाले अतिरिक्त रोजगार के अवसर (लाख श्रम दिवस) 11,053.69

गरीबों को जीवन की बुनियादी सुख-सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 12 घटकों को मिलाकर तैयार किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम वर्ष 1993-94 के दौरान जारी रहेगा।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के संबंध में वर्ष 1993-94 के लिए कुल आबंटन तथा लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :—

जोड़ (लाख रुपये)

	आबंटन	लक्ष्य
(1) आई आर डी पी	20508.00	4,97,156 (संख्या)
(2) जे आर वाई	71182.84	1779.57 (लाख श्रम दिन)

Proposal to set up National Legal Information Network

2512. SHRI SHIV PRATAP MISHRA : Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to set up a national legal information network for speedy and effective administration of justice in High Courts : and

(b) if so, the details of the proposal ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO) : (a) Yes, Sir.

(b) In pursuance of the successful computerisation of Daily Cause list preparation, Caveat Information System, Caselaw Information System, Judges Library Information System, and important Administrative applications such as Payroll, Personnel and General Administrative in the Supreme Court, National Informatics Centre (NIC) has initiated the Project Court Information System (COURTIS) for computerisation of all High Courts with the following objectives :

(i) To cut short delays in all time critical applications such as cause list preparation, Caveat matching and publication of Digests.

(ii) To electronically inter-connect all High Courts and Supreme Court through NIC's Satellite based Computer-communication network called NICNET.

(iii) To build up a nation-wide 'Caselaw databank' to provide computer aided legal research tools and creative search methods for finding precedents.

In Patna High Court and Delhi High Court the computerised systems are in use for the last three years. In AP High Court and Bombay High Court computerised systems have started working for the last one year. In Punjab and Haryana High Court, H.P. High Court, Karnataka High Court and Cuttack High Court the process of hardware installation is under way.

In the Calcutta High Court, Allahabad High Court, Ahmedabad High Court and Kerala High Court System Study Reports have been conducted and hardware is to be installed soon.

Status of 20-Point Programme

2513. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE : Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state :

(a) what is the status of 20-Point Programme in the restructured economy ;

(b) whether Government has fixed any targets under these programme; and

(c) if so, achievements made against targets set during 1991-92 and 1992-93 ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) The Twenty Point Programme 1986 continues to occupy the prime position it has enjoyed since its inception.

(b) Yes, Sir.

(c) The requisite information is given in the Annexure. [*See* Appendix CLXVIII, Annexure No 40]

आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किए जाने के लिए गुजरात द्वारा भेजी गई परियोजनाएं

2514. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किए जाने हेतु कोई परियोजनाएं /स्कीमें भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन परियोजनाओं/स्कीमों को विश्व बैंक की सहायता के दायरे से बाहर रखे जाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरीधर गोमांगो) : (क) और (ख) गुजरात सरकार द्वारा उसके आठवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय के रूप में प्रस्तावित 10,200 करोड़ रुपए के परिव्यय के विपरीत योजना आयोग ने राज्य सरकार के परामर्श से राज्य की आठवीं योजना के लिए 11,500 करोड़ रुपए का परिव्यय नियत किया है । राज्य सरकार द्वारा उसकी आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के लिए प्रस्तावित परिव्यय के पूरे ब्यौरे योजना दस्तावेज में उपलब्ध है जिसे संसद पुस्तकालय में रख दिया गया है ।

(ग) गुजरात में विश्व बैंक की सहायता से सत्रह परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जाना

2515. **श्री राम जेठमलानी** :

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वृद्धि दर के संबंध में निर्धारित किये गए लक्ष्यों को इस योजना के पहले दो वर्ष में पूरा नहीं किया जा सका था;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) पिछले दो वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के स्वरूप में कतिपय परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ङ) विगत दो वर्षों के दौरान वृद्धि दर के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति न होने कारण देश को हुई क्षति को पूरा करने के लिए क्या सरकार का योजना के शेष बचे वर्षों के लिए लक्ष्यों को पुनः निर्धारित करने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरीधर गोमांगो) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के पांच वर्ष की अवधि के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की लक्षित विकास दर औसतन 5.6 प्रतिशत है । केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी एस ओ) के अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 1992-93 में अर्थात् योजना के प्रथम वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में विकास लगभग 4.2 प्रतिशत होने की संभावना है । 1993-94 के लिए अनुमान उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ) पंचवर्षीय योजनाएं वार्षिक योजनाएं द्वारा परिचालित की जाती है जिन्हें चालू वार्षिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है ।

(ङ) पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को केवल पांच वर्ष की अवधि के औसत पर तैयार किया जाता है न कि वार्षिक आधार पर । आठवीं पंचवर्षीय योजना के विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर लिए जाने की सम्भावना है ।

Performance of projects under monitoring

2516. DR. SANJAYA SINH : Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state :

(a) the total number of projects under monitoring as on date which were progressing ahead of schedule, the total number of projects which were on schedule and the total number of projects which were behind schedule; and

(b) the cost escalation as on date of the projects under monitoring ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) As on 1-4-93, three hundred and fifty three (353) projects are under monitoring. Of these, one (1) project is ahead of the schedule, 165 projects are on schedule and 187 projects are behind schedule with respect to their latest approved dates of commissioning.

(b) The average cost escalation in all the 353 projects under monitoring is 38.9% with respect to their latest approved costs.